अधिगम
अंक 20 : सितम्बर 2021

इजराइल-फिलिस्तीन के प्रति भारतीय नीति : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

डॉ० सोनाली सिंह*

सार :

इजराइल–फिलिस्तीन विषयक भारतीय विदेश नीति का विकास 1947 के पश्चात विभिन्न चरणों में एवं विभिन्न परिस्थितियों के प्रभावाधीन हुआ है। प्रथम चरण का आरंभ 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना एवं भारत द्वारा उसे मान्यता देने के साथ शुरू हुआ। यद्यपि भारत ने इजराइल को एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी परंतु 1956 के स्वेज संकट के समय से इजराइल की आक्रामक एवं विस्तारवादी प्रवृत्ति के कारण उसके साथ प्रत्यक्ष संबंध विकसित नहीं हो सके जबकि अप्रत्यक्ष रूप से अरब देशों के साथ कूटनीतिक एवं राजनीतिक समझ में मजबूती आई। अरब देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैये के बावजूद भारत की इजराइल के प्रति नीति अरब देशों से अलग थी, क्योंकि वे देश इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार नहीं करते थे एवं येन केन प्रकारेण उसको नेस्तनाबूद करने पर आमादा थे। भारत इस तरह के दृष्टिकोण के सर्वथा विरुद्ध था और वह अरब इजराइल के मध्य विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का पक्षधर था। फिलिस्तीनी अस्तित्व एवं उसकी अस्मिता के रक्षार्थ फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पी.एल.ओ. की भूमिका के संबंध में अरब देशों के बीच सर्वसम्मति का अभाव था जिसके कारण प्रारंभ में भारत ने फिलस्तीनी मुद्दे पर पी.एल.ओ. की जगह अरब देशों के समर्थन की नीति अपनाई। दूसरे दौर में विशेषतः 1973 में अरब इजराइल युद्ध के पश्चात भारत की नीति अरब देशों को समर्थन प्रदान करने के स्थान पर स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के उद्देश्य के लिए संघर्षरत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन एवं उसके नेता यासिर अराफात को समर्थन देने की हो गई।। इसका कारण

* पूर्व शोध छात्रा, गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, झूँसी, प्रयागराज

यह था कि 1974 में रबात पैन अरब शिखर सम्मेलन में पी.एल.ओ. को फिलिस्तीनी उद्देश्य का सर्वमान्य प्रतिनिधि स्वीकार किया गया था । भारत का यह कदम ओस्लो शांति संधि एवं इसराइल–फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापना हेतु जारी पहल की दृष्टि से सकारात्मक था। तीसरे दौर में, भारत ने 1992 में इजराइल को कूटनीतिक मान्यता प्रदान की एवं फिलिस्तीन को राजनीतिक, कूटनीतिक एवं आर्थिक समर्थन देना जारी रखा। शीतयुद्ध उत्तरकालीन वैश्विक परिदृश्य में आए बदलाव एवं पश्चिम एशिया के राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक वातावरण में आए परिवर्तनों ने भारत की इजराइल और फिलिस्तीन विषयक नीति में आधारभूत परिवर्तन किया। इसके तहत भारत ने दोनों देशों के साथ गुण व अवगुण के परीक्षण के परिणामस्वरूप संबंधों को साधने पर बल दिया। यह एक सजग संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित नीति की दिशा में पहल थी जिसके तहत भारत ने राष्ट्रीय हित तथा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दोनों देशों के साथ स्वतंत्र नीति के अनुपालन पर जोर दिया। भारत के लिए दोनों देशों के साथ स्वतंत्र नीति का अनुपालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत अपनी प्रतिरक्षा एवं तकनीक विशेष जरूरतों हेतु इजराइल की अनदेखी नहीं कर सकता एवं अपनी ऊर्जा आवश्यकता, खाड़ी के देशों में कार्यरत अधिकाधिक संख्या में भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा में खाड़ी के देशों के समर्थन की भी आकांक्षा रखता है। इसलिए भारतीय नीति व्यवहारवादी संतुलन के आधार पर एक तरफ जहाँ पश्चिमी एशिया की क्षेत्रीय शक्तियों जैसे सऊदी अरब एवं ईरान इत्यादि को साधने की है, वहीं इजराइल के साथ रक्षा, प्रतिरक्षा एवं तकनीक विशेष जरूरतों हेतु संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु प्रयत्नशील हैं ।

महत्त्वपूर्ण शब्दः पी.एल.ओ., साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शांति–प्रक्रिया, पवित्र भूमि, पूर्वी जेरूसलम, फिलिस्तीन , यहूदी राज्य –

इजराइल–फिलिस्तीन विवाद से भारतीय जुड़ाव उपनिवेशकालीन दौर से रहा है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान सन् 1920 में खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रवादियों ने अरब समुदाय से सहानुभूति प्रदर्शित की तथा उनके उद्देश्य एवं लक्ष्यों का पुरजोर समर्थन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं– महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने फिलिस्तीन समस्या एवं "पवित्र भूमि" को लेकर अरब एवं यहूदियों के बीच होने वाले संघर्ष के प्रति गहरी

रुचि दिखाई। सन 1938 में महात्मा गांधी ने फिलिस्तीनी समुदाय के पक्ष में यह कहा कि, "फिलिस्तीन अरबों से उसी तरह संबंधित है जैसे इंग्लैंड इंग्लैंडवासियों से और फ्रांस फ्रांसीसी लोगों" से। 15 अगस्त 1947 को भारतीय उपमहाद्वीप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अवसान के उपरांत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु बने। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनी समुदाय के हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाले नेताओं की पंक्ति में शामिल होने एवं तत्कालीन घरेलू, राजनीतिक, आर्थिक एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भारत ने स्वातंत्र्योत्तर काल में पूर्ववत् फिलिस्तीनी समर्थन की नीति को जारी रखा। सन 1948 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन एवं यहूदी राज्य के रूप में इजराइल की स्थापना का विरोध किया। भारत कुल 13 देशों में से एकमात्र गैरअरब देश था जिसने फिलिस्तीन का समर्थन किया। फिलिस्तीन के विभाजन के विरोध के बावजूद भारत ने सितंबर 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी परंतु उसने इजराइल के साथ राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध बहाल नहीं किए। इजराइल को मान्यता दिए जाने के संदर्भ में पंडित जवाहर नेहरू ने तर्क दिया कि, "इजराइल की स्थापना अब एक स्थापित तथ्य है इसे स्वीकार नहीं करने का तात्पर्य है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों राष्ट्रों के बीच विद्वेष को बढ़ावा देना।"

इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भारत द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन करने का बुनियादी आधार उसके विदेश नीति के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ था। भारत ने अपने विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत साम्राज्यवाद एवं नस्लवाद का विरोध, वैश्विक स्वाधीनता संग्राम को समर्थन, सैन्यबल आधारित कब्जा एवं विस्तार का विरोध तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को स्वीकार किया था। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन हेतु अपनी उद्देश्यपरक प्रतिबद्धताओं के कारण भारत ने फिलिस्तीनी उद्देश्य को समर्थन प्रदान किया। भारत की नीति से जुड़े कुछ व्यावहारिक पहलू भी थे जिसकी अनदेखी उसके द्वारा नहीं की जा सकती थी। प्रथम, भारत ने धार्मिक आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन (द्विराष्ट्र सिद्धांत) की प्रस्थापना को कभी मान्यता नहीं दी। अतः फिलिस्तीनी क्षेत्र के धार्मिक आधार पर विभाजन की प्रक्रिया को समर्थन देने का तात्पर्य अपने पंथनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र विषयक आधारभूत मूल्यों तथा साम्राज्यवाद एवं विस्तारवाद विरोधी सिद्धांतों की अवहेलना होती। दूसरा,

पाकिस्तान खाड़ी के देशों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध एक पैन इस्लामिक संगठन बनाने हेतु प्रयासरत था। इस हेतु वह कश्मीर समस्या को आधार बनाकर भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को राष्ट्र के प्रति निष्ठा से भ्रमित कर उनके अंदर पैन इस्लामिक भावना का संचार करना चाहता था जो कि देश की एकता एवं अखंडता को विघटित करने वाली कार्यवाही होती। तीसरा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों हेतु खाड़ी के अरब देशों पर निर्भर था जो कि फिलस्तीनी हितों के समर्थन को लेकर एकजुट थे। अतः फिलस्तीन के समर्थन के विपरीत नीति अपनाने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित होने का खतरा था। चतुर्थ, पंडित नेहरू सहित यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो एवं मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से थे एवं नेहरू का नासिर एवं अरब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था जिसके कारण इजराइल के साथ भारत के खुले एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित नहीं हो सके।

1953 में इजराइल के साथ संबंधों में सुधार की दृष्टि से मुंबई में एक दूतावास की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य इजराइल के नागरिकों एवं तीर्थ यात्रियों को वीजा प्रदान करना था परंतु इजरायली राजदूत द्वारा एक समाचार पत्र में भारत की विदेश नीति की आलोचना करने के कारण उसे बंद कर दिया गया। इजराइल–फिलिस्तीन संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम मिस्र के राष्ट्रपति नासिर द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण घटित हुआ। नील नदी पर बनने वाले आसवान बांध के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा वापस किए जाने के कारण राष्ट्रपति नासिर द्वारा यह कदम उठाया गया। इस गतिरोध की स्थिति के समाधान हेतु मिस्र, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच वार्ता विफल रही क्योंकि राष्ट्रपति नासिर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने मिस्र के सिनाई क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इजराइल के इस कदम की तीव्र भर्त्सना की। इस घटना के संदर्भ में भारत की इजराइल के प्रति नीति को तीन कारणों ने प्रभावित किया। प्रथम, उपनिवेशवाद के विरोध पर आधारित एशिया अफ्रीका सौहार्द, द्वितीय, इजराइल की साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ बढ़ती निकटता एवं तृतीय, नव स्वतंत्र राष्ट्रों से बढ़ती दूरी तथा नेहरू नासिर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध।

अरब इजराइल के बीच सीमा विवाद ने पश्चिम एशिया में एक अन्य युद्ध संकट को जन्म दिया। इजराइल ने सिनाई, गाजा, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी जेरूसलम के क्षेत्र को अरबों से बलात हस्तगत कर लिया। भारत ने इस संदर्भ में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन की नीति अपनाई। इसी प्रकार 6 अक्टूबर 1973 को चौथे अरब–इजराइल संघर्ष के दौरान भारत ने फिलिस्तीन समर्थक रुख अपनाया। इस समय मिस्र तथा सीरिया ने 1967 में इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस लेने के लिए संयुक्त रूप से इजराइल पर आक्रमण किया परंतु भारत ने इस कार्रवाई के लिए इजराइल को दोषी माना क्योंकि उसने अरबों की जबरन हस्तगत की गई भूमि को वापस करने से मना कर दिया। 1973 के युद्ध के पश्चात भारत की अरब देशों के प्रति समर्थन की नीति फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पी.एल.ओ.) एवं उसके नेता यासिर अराफात को समर्थन देने पर केंद्रित हो गई। अल्जीरिया घोषणा के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव को सह–प्रायोजित किया जिसके तहत फिलिस्तीन विषय पर पी.एल.ओ. एवं उसके नेता यासिर अराफात को सर्वमान्य पक्षकार के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1974 में पी.एल.ओ. को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया जिसको भारत का समर्थन प्राप्त था।

1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो यह कयास लगाए जाने लगे कि भारत की फिलिस्तीन नीति में बदलाव आएगा परंतु पश्चिम एशिया के प्रति परंपरागत नीति बदस्तूर जारी रही। जनता पार्टी सरकार ने अरब विशेषतः फिलिस्तीनीयों के संघर्ष को समर्थन प्रदान किया एवं अरब इजराइल विवाद के निस्तारण हेतु चलने वाली शांति प्रक्रिया को यथोचित एवं आवश्यक बताया। इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि पर इजराइली अधिवास एवं इजराइली बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया विषय पर जनता पार्टी की सरकार ने वक्तव्य दिया कि," भारत किसी देश द्वारा बल प्रयोग के आधार पर भूभाग कब्जा करने की कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना करता है। इसलिए भारत इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि एवं उस पर स्थापित इजराइली बस्तियों के नियमितीकरण एवं स्थायीकरण के सख्त खिलाफ है।"

17 सितंबर 1978 को इजराइल एवं मिस्र के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ जिसकी पी.एल.ओ. एवं अरब समुदाय ने कड़ी भर्त्सना की। मिस्र पर आरोप लगाया गया कि इसने इजराइल के साथ स्वतंत्र संधि

करके अरब सौहार्द एवं एकजुटता को खंडित करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण अरब समुदाय समर्थित था। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, "भारत कैंप डेविड समझौते को समर्थन प्रदान नहीं करता क्योंकि इसमें तीन कमियाँ है"। प्रथम, मध्यपूर्व में फिलिस्तीन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है एवं इस क्षेत्र में स्थाई शांति तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक फ़िलस्तीनी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जाता। द्वितीय, इजराइल एवं मिस्र ने पी.एल.ओ. को फिलिस्तीन के प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता नहीं दी है। तृतीय, कैंप डेविड समझौता पूर्वी जेरूसलम के मुद्दे पर मौन है। कैंप डेविड समझौते के उपरांत एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत अरब देशों ने मिस्र के खिलाफ लामबंद होकर उसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बर्खास्त करने का प्रयास किया। सितंबर 1979 में हवाना सम्मेलन में भारत ने मिस्र का समर्थन किया एवं अरब देशों के इस रुख को अस्वीकार किया। भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री एस.एन. मिश्रा ने कहा कि, "इजराइल मिस्र के बीच हुए समझौते ने अरब समुदाय के बीच समन्वय एवं सौहार्द को नुकसान पहुंचाया है। अब यह मिस्र की जिम्मेदारी है कि वह इस नुकसान की भरपाई करे एवं पूर्वस्थिति को स्थापित करे।"

1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आईं और फिलिस्तीनी आंदोलन को समर्थन देने की परंपरागत भारतीय नीति को जारी रखा। तत्कालीन विदेश मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने 26 मार्च 1980 को संसद में यह घोषणा की कि, "भारत ने नई दिल्ली मे पी.एल.ओ. के कार्यालय को पूर्ण कूटनीतिक मान्यता देते हुए एक दूतावास की स्थापना का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत राजदूतों को प्राप्त विशेष अधिकारों एवं उन्मुक्तियों को भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।" भारत के इस दृष्टिकोण के समर्थन में यासिर अराफात ने 28 से 30 मार्च 1980 के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा की एवं उनके सम्मान में दिए गए रात्रिभोज के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा कि," फिलिस्तीनियों के प्रति भारतीय सहानुभूति शुरू से ही भारतीय विदेश नीति का अंग रही है। मध्य पूर्व में इस संकट का शांतिपूर्ण एवं व्यापक समाधान तभी संभव है जब पी.एल.ओ. इस प्रक्रिया में समान रूप से सहभागिता करे। भारत द्वारा पी.एल.ओ को पूर्ण कूटनीतिक दर्जा दिया गया जोकि भारतीय हितों के लिए तीन प्रकार से महत्त्वपूर्ण था। प्रथम, अरब

समुदाय में मौजूद उग्रपंथी समूहों को समर्थन देना जिससे धार्मिक कट्टरवादी समूहों के प्रति संतुलित किया जा सके। यह कट्टरपंथी समूह इजराइल–फिलिस्तीन विवाद जो कि एक राजनीतिक समस्या थी उसे धार्मिक रंग देकर इजराइल के विरुद्ध जिहादी अभियान हेतु प्रयासरत थे। द्वितीय, भारत यासिर अराफात द्वारा फिलिस्तीन समस्या के निस्तारण हेतु उदारवादी प्रयासों से भी प्रभावित था तृतीय, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के संदर्भ में भारत को अरब देशों के साथ अपनी प्रारंभिक नीति भी स्पष्ट करनी थी। फिलिस्तीन के प्रति भारतीय नीति को और मजबूती तब मिली जब यासिर अराफात 1982 में निर्वासित राज्य अध्यक्ष के रूप में भारतीय दौरे पर आए। यह यात्रा विशिष्टतः इजराइल द्वारा लेबनान पर आक्रमण की धमकी, ईरानी क्रांति, क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक भावना में उभार एवं अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के संदर्भ में हुई । जून 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया जिसे इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीनी आंदोलन को समाप्त करने वाली कार्रवाई बताई। मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित सातवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत द्वारा एक संदेश जारी किया गया जिसमें फिलिस्तीनी आंदोलन का समर्थन एवं फिलिस्तीनी भूभाग पर इजराइली कब्जे का विरोध किया गया।

सत्ता ग्रहण करने के 5 महीने बाद राजीव गांधी ने मिस्र की यात्रा की तथा फिलिस्तीनियों के प्रति भारतीय समर्थन की नीति को दृढ़तापूर्वक स्पष्ट किया। 1985 में जब इजराइल ने ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में फिलिस्तीनी मुख्यालय पर बमबारी की तो भारत ने इस कार्रवाई को आक्रामक एवं विस्तारवादी बताते हुए इसे शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता हेतु एक बड़ा खतरा बताया। पी.एल.ओ. प्रमुख यासिर अराफात एवं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री को तरफ से एकजुटता एवं समर्थन का संदेश प्रेषित किया गया। हालांकि भारत अरब देशों के साथ उस अभियान में शामिल नहीं हुआ जिसमें इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से बर्खास्त करने के लिए प्रयास किया गया।

इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के विरुद्ध अपनाई जाने वाली कठोर एवं दमनात्मक नीति के विरोधस्वरूप दिसंबर 1987 में गाजा एवं वेस्ट बैंक में फिलस्तीनी इंतेफदा (विद्रोह) का उत्कर्ष हुआ। भारत ने पश्चिम एशिया के प्रति अपनी परंपरागत नीति के अनुरूप फिलिस्तीनी लक्ष्य को समर्थन देना जारी रखा। इंतेफदा का परिणाम नवंबर 1988 में अल्जीरिया घोषणा

के अंतर्गत आया जिसमें पी.एल.ओ. ने 1947 के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हुए फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा की। भारत उन अग्रपंक्ति के राष्ट्रों में था जिसने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी एवं पी. एल.ओ. के अध्यक्ष यासिर अराफात का राज्याध्यक्ष की हैसियत से भारत में स्वागत किया। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में भारत ने इजराइल में होने वाले डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया । पी.एल.ओ. के नेताओं ने भारत के इस कदम की सराहना की जो सदैव से फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना के उनके लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहा है।

अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के पश्चात पश्चिम एशिया की परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया। इस काल में घटित घटनाओं में विश्व मानचित्र से सोवियत संघ का अवसान, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व की दस्तक तथा पी.एल.ओ. द्वारा इराकी शासक सद्दाम हुसैन को दिए जाने वाले समर्थन के कारण उसके राजनीतिक प्रभाव में ह्रास इत्यादि प्रमुख थे। सन् 1991 में अमेरिका ने इराक को कुवैत से बाहर निकाल कर मध्य पूर्व में शांति स्थापना हेतु "अंतरराष्ट्रीय मध्यपूर्व शांति सम्मेलन" के लिए पहल की। इस प्रकार की गतिविधियों ने पश्चिम एशिया में एक नए युग का सूत्रपात किया। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत सन 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने तेलअवीव (इजराइल) में एक कूटनीतिक मिशन की स्थापना की एवं गाजा में भी एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला जो बाद में फिलिस्तीनी आंदोलन के दो भागों में विभाजित (हमास एवं पी.एल.ओ.) होने के पश्चात 'रामल्ला' में स्थानांतरित कर दिया गया ।1992 से ढाई दशक तक भारत इजराइल संबंधों में सुधार हुए हैं विशेषकर रक्षा, विज्ञान तकनीक एवं कृषि के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। एन.डी.ए. प्रथम के शासनकाल में इजराइल के साथ उच्चस्तरीय औपचारिक यात्राओं का दौर आरंभ हुआ। सन 2000 में लालकृष्ण आडवाणी भारत के प्रथम मंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। उसी वर्ष विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी इजराइल की यात्रा पर गए जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच 'आतंकवाद विरोधी संयुक्त तंत्र' की स्थापना की गई। सन् 2003 में एरियल शेरोन प्रथम इजराइली प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की। सन् 2003 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे इजराइल के विरुद्ध प्रस्तावित किया

गया। यह प्रस्ताव इजराइल के विरुद्ध उसके द्वारा विवादित क्षेत्र में एक अलग दीवार खड़ी करने के मामले में लाया गया था। सन् 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण यूनेस्को की पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव को भी समर्थन प्रदान किया। सन् 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव को भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा सह–प्रायोजित किया गया जिसके तहत फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का एक गैरसदस्य एवं गैरमतदाता पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के एक दशक के कार्यकाल में भारत एवं फिलस्तीन के बीच संबंध सौहार्द पूर्ण रहे। फिलिस्तीनी सत्ता प्रमुख महमूद अब्बास क्रमशः 2005, 2008, 2010 एवं 2012 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में खासा प्रयास किया। इसका संकेत तब मिला जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् द्वारा पारित उस प्रस्ताव के मतदान हेतु भारत अनुपस्थित रहा जिसे एचआरसी उच्चायुक्त ने 2014 में गाजा में हुए हवाई हमले में इजराइल और हमास द्वारा किए गए युद्ध अपराध एवं मानव संहार विषयक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 2016 में भारत पुनः मानवाधिकार परिषद् के प्रस्ताव हेतु मतदान में अनुपस्थित रहा जो इजराइल की आलोचना से संबंधित था। भारतीय नीति में बड़ा बदलाव ऐतिहासिक शहर जेरूसलम के विषय में हुआ जिस पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों दावा करते हैं। यह बदलाव भारतीय नीति में तब स्पष्ट हुआ जब पी.एल.ओ अध्यक्ष महमूद अब्बास 2017 में भारतीय दौरे पर आए। इसके पूर्व विभिन्न संयुक्त वक्तव्य में भारत ने दो राज्य आधारित समाधान का समर्थन किया एवं पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता दी। महमूद अब्बास की यात्रा के दौरान जारी भारतीय आधिकारिक वक्तव्य में दो राज्य आधारित समाधान के साथ पूर्व जेरूसलम का उल्लेख नहीं था। सन् 2015 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी इजराइल की यात्रा पर गए। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो सर्वप्रथम "रामल्लाह" गए एवं "पवित्र शहर" को स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में सहमति दी। फरवरी 2018 में इजराइल की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जहां उनके यात्रा पथ में "रामल्लाह" शामिल नहीं था। इसके पश्चात जारी आधिकारिक वक्तव्य मे पूर्वी जेरूसलम का उल्लेख न किया जाना फिलिस्तीन के प्रति भारतीय नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत था।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने फिलिस्तीनी समर्थक एवं इजराइली विरोधी जिस नीति का अनुपालन किया उसके एवज में कश्मीर समस्या एवं पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अरब देशों से यथोचित समर्थन एवं सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। भारत द्वारा पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य, अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं शांति आधारित जिस नीति का अनुसरण फिलिस्तीनियों के सहयोग हेतु किया उसका प्रतिफल खाड़ी के देशों ने धर्म आधारित संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना के रूप में दिया। शीतयुद्ध उत्तरकालीन विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे फोरम्स की घटती लोकप्रियता एवं यथार्थ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में भारत ने इजराइल के साथ सहयोग में वृद्धि की। इजराइल ने जहाँ रक्षा एवं तकनीक के क्षेत्र में सहयोग कर भारत को आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने में सहयोग किया वहीं कृषि इत्यादि क्षेत्रों में रचनात्मक सहयोग की दिशा में संबंधों के नए आयाम विकसित हुए।

शीत युद्ध उत्तर काल में इजराइल–फिलिस्तीन के प्रति भारतीय नीति संतुलन आधारित दृष्टिकोण के आधार पर आकार लेने लगी। भारत ने एक तरफ जहाँ फिलिस्तीन के सरोकारों को यथोचित राजनीतिक व कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया वहीं इजराइल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु प्रयास किए। भारतीय नीति का इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति झुकाव केंद्र में आने वाली सरकार के दृष्टिकोण से प्रभावित रहा। कांग्रेस या उसके समर्थन से बनी सरकारों ने जहाँ फिलस्तीनी पक्ष के प्रति झुकाव की नीति अपनाई वहीं पर एनडीए के कार्यकाल में भारतीय नीति इजराइल के प्रति उन्मुख होती प्रतीत होती है। वर्तमान में भारत अरब–इजराइल के विषय में डिहाइफनेशन की नीति या सजग संतुलनकारी नीति पर अग्रसर है जिसके अंतर्गत परिस्थितिगत आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों का आकलन करते हुए दोनों देशों के साथ स्वतंत्र एवं सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना करना है ।

Reference

- For detail account of India*s foreign policy see Bandopadhyay J-] (2003)] The Making of India*s Foreign Policy] Allied Publishing% New Delhi-

- Tripathi] Sasmita (2013)] Þ India*s Policy Towards Palestine% A Historical Perspectiveß] The Indian Journal of Political Science] Vol74(no-1)] pp-124&138-
- Kumaraswami] R-P-(1995)] India*s Recognition of Isreal] Middle Eastern Studies] Vol-31 (noi-01)] pp-124&138-
- Sharma] P- Jagdish (1992)] Þ India and Isreal% A Study of Evolution in Relation (1948&92) Proceeding of Indian History Congress] 1992] Vol 53(1992)] pp-593&597-
- Singh] Rajan]S- (2001)] Þ India and Isreal% Towards Greater Cooperationß] Indian Quarterly] Vol-57 (no-04)]pp-113&148-
- Srivastava] R-K- (1970)] ÞIndia Isreal Reations] The Indian Journal of Political Science] Vol- 31 (no-04)] pp-238&264-
- EÛplained% How Has India*s Policy on Isreal and Palistine Evolved over Time] The Indian EÛpress] June 2] 2021-
- Balancing Act on India*s Stand on Isreal Palestine Conflict] The Hindu]21 May] 2021-
- Kapur Manvi] How India*s Relations with The Isreal and Palestine Changed from Nehru to Modi] Quartz India] May 21] 2021-
- Kumarswamy] P-R-] India*s New Isreal Policy] SWP] March 1] 2019-
- Khanna] V-N-] (2018)] Foreign Policy of India] Vikas Publishing House%Noida (Uttar Pradesh)-
- Malone] M- David (2011)] Does Elephant Dance% Contemporary Indian Philosophy] OÛfordbUniversity Press% New Delhi-